संख्या:18/2018/252/छप्पन-2018-180क्यू/81

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2018

विषय: राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों, ग्राउण्ड सपोर्ट एक्यूपमेन्ट के क्रय व उनके अनुरक्षण तथा आयल/लुब्रीकेन्ट्य/ए0टी0एफ0 व ए0वी0 गैस आदि के लिए मेसर्स एच0ए0एल0, बंगलौर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को अग्रिम आहरण का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 868/ना0उ0नि0/6-जी/88, दिनांक 31 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-35/2017/35/छप्पन-2017-180क्यू/81 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंगित शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2017 द्वारा राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों, ग्राउण्ड सपोर्ट एक्यूपमेन्ट के क्रय एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों के नाम स्टेट बैंक आफ इंडिया में " लेटर आफ क्रेडिट " खोलने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को एक मामले में रूपये 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र) तक का अग्रिम आहरण की स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिये प्रदान की गयी है। उक्त समाप्त हो रही अवधि की तिथि को बढ़ाकर अब श्री राज्यपाल महोदय आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 तक रूपये 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण की तथा इतनी ही धनराशि के पुर्जो को नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति का अधिकार प्रदान करते हैं।

2- श्री राज्यपाल महोदय राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के लिए आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि के क्रय हेतु भारत सरकार के उपक्रम इंडियन आयल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान करने हेतु उन्हें एक मामले में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण तथा इतनी ही धनराशि का आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि का क्रय नियमानुसार करने का अधिकार भी निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) अग्रिम आहरण, अग्रिम आहरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं संख्या- ए-1-235/दस-15-1-(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में दी गई शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) मामले में दूसरा अग्रिम तभी आहरित किया जाए, जब पूर्व आहरित अग्रिम का पूर्ण समायोजन हो जाने पर समायोजन बिल महालेखाकार को भेज दिया जाय। अग्रिम से सम्बन्धित प्रत्येक बिल पर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त आशय का एक प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा। जिस धनराशि का समायोजन नहीं हुआ उस सीमा तक अग्रिम की धनराशि का आहरण प्रतिबन्धित हो जाएगा। गत वर्ष के अग्रिमों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

(3) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप यदि शासन को कोई क्षति होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं आहरण-वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) अग्रिम जिस सामग्री के क्रय के लिए किया जा रहा है, उसकी आपूर्ति एवं अग्रिम का समायोजन उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं दिनांक 10.6.2011 की व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

(5) फालतू पुर्जो के क्रय तथा आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0/ए0वी0 गैस आदि के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो और क्रय की स्वीकृति के आदेश में उस प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है।

(6) आपूर्तिकर्ता/फर्म/कम्पनी/उत्पादक को अग्रिम भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक बैंक गारन्टी आदि प्राप्त करने के बाद लेकर किया जाए।

(7) यह अधिकार केवल दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन अग्रिम आहरण से सम्बन्धित प्रत्येक स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे कि "सम्बन्धित मद में बजट में कितना प्रावधान उपलब्ध है उसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितनी धनराशि सम्बन्धित व्यय को वहन करने हेतु उपलब्ध है।" किसी भी दशा में व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं किया जाए।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:एफ0 ए0-1-38/दस-2018, दिनांक 27 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0 संख्या:18/2018/252(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अग्रिम बिल पारित करते समय सुनिश्चित कर लें कि मामले में उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1

(5) सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।